जोधपुर-पाली-मारवाड़ कंकाणी को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित करेंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी तथा स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, नोडल विभाग होंगे।

जयपुर, 4 फरवरी। जैसे-जैसे देश डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए बड़ी आवश्यकता के रूप में उभरी है। इसको और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बड़ी पहल की है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाएगी। इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार जोधपुर-पाली-मारवाड़ और कंकाणी सहित अन्य उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स घोषित करेगी। इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए फास्ट-ट्रेक लैण्ड अलॉटमेंट, यूटिलिटी कॉर्डिनेशन और सिंगल विण्डो रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगी। इस नीति के अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान दिए जाएंगे। यह नीति सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ ावा देगी और उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित भी करेगी।

प्रदेश में निवेशकों को सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना के लिए राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए दो समितियों-स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी (एसएलएएफसी) और स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

संसद में भारी हंगामा, प्रमंत्री भाषण नहीं दे सके

नई दिल्ली, 04 फरवरी। सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होने वाला भाषण भी टल गया है। प्रधानमंत्री मोदी को आज शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। इससे पहले सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सदन की कार्यवाही 12 बजे, फिर 2 बजे, और इसके बाद शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक गद्दार जा रहा है। इसका चेहरा देखो।" इसके बाद उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए कहा, "हैलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे।"

मंत्री ने गांधी से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए कहा, "देश के दुश्मन।" यह बातचीत उनके उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने (बिट्टू) प्रदर्शनकारी सांसदों के बारे में कहा था कि " वे ऐसे बैठे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो।"

ममता बनर्जी ने सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ पर, यह महसूस करते हुए कि अगर, संशोधित वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई तो तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में ''ड्रामा'' करने का निर्णय लिया। अगर, सुप्रीम कोर्ट इस ''ड्रामे'' से प्रभावित होकर, एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित कर देता है तो प्रजातंत्र के लिए काला दिन होगा।

इसका चुनाव पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है।

बनर्जी और उनकी पार्टी ने बंगाल में फर्जी मतदान करने की कला में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने मतदाता सूचियों की खामियों का फायदा उठाकर कई सीटों पर जीत हासिल की थी। टीएमसी को मतदाता सूचियों में मौजूद फर्जी नामों की पूरी जानकारी रहती थी और वह नियमित रूप से अपने समर्थकों को फर्जी मतदान के लिए भेजती थी।

कम से कम 56 लाख नाम ऐसे पहचाने गए हैं जो फर्जी थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी हटाए गए, जिनके नाम पर दर्ज लोग बहुत पहले मर चुके थे। इसके साथ-साथ बांग्लादेश से सीमा पार कर आए अवैध प्रवासी भी बंगाल के चुनावों में नियमित रूप से मतदान करते रहे थे।

इन सभी समूहों को मिलाकर देखा जाए तो मतदाता सूची का सही और ईमानदार संशोधन बड़ी संख्या में फर्जी और अवैध मतदाताओं को हटाने का कारण बन सकता है, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ममता बनर्जी को ऐसे फर्जी वोटों से फायदा मिलता रहा है और अब उन्हें इसमें समस्या दिखाई दे रही है। इसलिए वह इस प्रक्रिया को बदनाम करने और खत्म करने की कोशिश कर रही हैं।

दुर्भाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय इस चुनौती का सामना नहीं कर पाया और ऐसा लगता है कि वह उनके राजनीतिक दबाव के आगे झुक गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के राजनीतिक दांव का सामना नहीं कर पाता और मतदाता सूची का सही संशोधन खतरे में पड़ जाता है, तो यह लोकतंत्र और मतदान के लिए दुखद दिन होगा।

अदालत में उनके राजनीतिक भाषण को रोकने के बजाय, जज उनके दबाव वाले तरीके के सामने झुक गए और उन्हें लगभग पंद्रह मिनट तक बोलने दिया। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया कि वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, जैसे विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में अपनाई जा रही पद्धितयों, पर ध्यान दें।

अदालत तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर आगे सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में नामों में छोटे-मोटे अंतर के आधार पर लोगों के नाम मतदाता सूची से मनमाने तरीके से हटाए जा रहे हैं।

बनर्जी ने नाम और उपनाम लिखने के अलग-अलग तरीकों की ओर ध्यान दिलाया, जो वर्तमान व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे किसी भी अंतर के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।

चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैंच ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर के तहत नोटिस सावधानी से भेजे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ईसीआई को, कृपया नोटिस सावधानी से भेजें। आप प्रतिष्ठित लेखकों आदि को नोटिस नहीं भेज सकते।"

ये टिप्पणियां उस घटना के कुछ हफ्तों बाद आई हैं, जब चुनाव आयोग ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त), नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित कई सार्वजनिक हस्तियों को एसआईआर के तहत नोटिस भेजे थे।

ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महिलाओं के नाम केवल इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपना सरनेम बदल लिया। उन्होंने कहा, "मान लीजिए बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाती है, वह पति का सरनेम इस्तेमाल कर रही है, इसे भी मिसमैच माना गया, कुछ बेटियां ससुराल चली गईं, उनके नाम भी हटा दिए गए।"

युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मु.मंत्री पद की शपथ ली

■ कुकी समुदाय के भाजपा विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री बनाया गया

इंफाल, 04 फरवरी। हिंसाग्रस्त मणिपुर को लंबे राष्ट्रपति शासन के बाद अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मार्शल आर्ट के धुरंधर मैतेई समुदाय के युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली। इससे पहले आज उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया।

वहीं, भाजपा विधायक नेमचा किपगेन ने मणिपुर के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। किपगेन कुकी समुदाय से हैं। इसके अलावा, नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भाजपा के गोविंदास कोंथौजम और एनपीपी केके लोकेन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। नेमचा किपगेन ने नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से डिजिटल माध्यम से शपथ ली। विधायक दल की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें खेमचंद (62 वर्षीय)को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में भाजपा विधायक दल की डेढ़ घंटे बैठक चली, जिसमें खेमचंद के नाम पर सहमति बनी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पर्यवेक्षक तरुण चुघ की उपस्थिति में भाजपा मुख्यालय में विस्तार से हुई विधायक दल की बैठक में कई नामों पर विचार हुआ था।

चर्चा थीकि कुकी बनाम मैतेई समुदाय के बीच संतुलन साधने के लिए नई सरकार में कुकी समुदाय को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री के मामले में लिए गए निर्णय से साफ थाकि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की पसंद को तवज्जो नहीं मिली। बीरेन सात बार के विधायक मैतेई समुदाय के ही गोविंद दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे।

भूमिगत ''चिकन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इस पट्टी की संवेदनशीलता को रेखांकित किया था। उनका कहना था कि इस हिस्से में किसी भी प्रकार का व्यवधान सैन्य आपूर्ति लाइनों को काट सकता है और सैनिकों की आवाजाही में बाधा डाल सकता है, साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को भी अलग-थलग कर सकता है। एनएफआर अधिकारियों के अनुसार, भूमिगत रेल ट्रैक आपात स्थितियों में भी निर्बाध सैन्य आवागमन सुनिश्चित करेगा। हाल के महीनों में बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव साफ़ तौर पर दिखाई दिया है। हाल ही में बांग्लादेश वायुसेना ने चीन के साथ ड्रोन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। रिपोर्टों के अनुसार, इन ड्रोनों में चीनी निगरानी तकनीक लगी होगी, जिसका उपयोग भारत-बांग्लादेश सीमा के 4,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र की निगरानी के लिए किया जा सकता है।

शरद पवार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजित पवार ने एनसीपी(एसपी) के साथ विलय की कोई पहल नहीं की थी।

शरद पवार ने कहा कि फडणवीस एनसीपी के दोनों गुटों के बीच हुई विलय संबंधी चर्चाओं का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

लोकसभाध्यक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिलचस्प बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने किताब की प्रति दिखा दी है। क्या यह वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है? स्थिति अब काफी कटु और खराब हो गई है और सत्तारूढ़ दल और राहुल गांधी के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस सत्र को सामान्य बनाना मुश्किल लग रहा है।

बोत्सवाना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की सफल बसाहट के बाद अब असम का जंगली भैंसा भी मध्यप्रदेश के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता नजर आएगा।

प.बंगाल चुनावों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य के दौरों के बाद सांसदों के साथ की जा रही ये वन-टू-वन बैठकें पार्टी की चुनावी रणनीति को और धार देने के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं।

चुनावों से पहले इस बैठक को भाजपा की डिनर डिप्लोमैसी के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य पार्टी के भीतर समन्वय को मज़बूत करना और पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक नैरेटिव को और तेज़ करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए कट-ऑफ पर्सेंटाइल को उस स्तर तक कम कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने असामान्य रूप से बहुत कम बताया है। इसमें कट-अफ पर्सेन्टाइल को शून्य और नकारात्मक तक कर दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए योग्यता मानकों को कम करना मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908